हरियाणा सरकार द्वारा बढाए गए बिजली बिलो के विरोध में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के मीडिया प्रभारी व कैथल स्थानीय विधायक श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी की अगुवाई में आज जवाहर पार्क से बिजली निगम दफ्तर तक रोष प्रकट किया गया और बिजली अधिकारी को विरोध पत्र दिया गया !

विरोध पत्र :-

1.हरियाणा प्रांत में चारों तरफ़ बिजली बिलो के विरुद्ध हाहाकार मचा है !गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के बिजली बिलो में भाजपा सरकार द्वारा 40-50 प्रतिशत की बेइंताशा वृध्दि कर दी गई है !लगभग यही हाल दुकानदारों,छोटे वाणिज्यक संस्थानों व लघु उधोगो का भी है,जो भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते बँद होने की कगार पर हैं !

छोटे से छोटे घर में रहने वाले साधारण व्यक्ति का बिजली का बिल प्रतिमाह रुपया 6000 से रुपया 10000 तक भाजपा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है !मध्यमवर्गीय परिवारों का बिजली बिल तो रुपया 15000 से रुपया 20000 तक आ रहा है !दुकानों,वाणिज्यिक संस्थानों और लघु उधोगों की स्थिति तो और भी बदतर है !

बिजली कम्पनी के अधिकारियों के कान पर जूँ तक नहीं रेंगती और वह भाजपा सरकार निर्धारित अमानवीय तौर पर बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते हैं !हरियाणा की जनता,खासतौर से शहरों में रहने वाले लोग भाजपा की सरकार का गठन करके अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं !

2.सबसे मुश्किल बात तो यह है कि भाजपा सरकार में बिजली कर्मचारियों के द्वारा घरों पर 'बिजली के छापेमारी 'अब रोजमर्रा की बात हो गई है !शहरवासी खौफ के साये में दिन प्रतिदिन जीते हैं कि कब बिजली विभाग के अधिकारी छापेमार दस्ते सहित घर पर हमलावरो की तरह पहुँच जायेंगे !दुर्भाग्य से शायद ही कोई मोहल्ला या गली इस बिजली के छापेमारी दस्तों से अछूती हो !कैथल शहर व जिले में तो यह स्थिति ओर ज्यादा विषम है,जैसे की भाजपा सरकार कैथल शहर व जिले के लोगों से भाजपा का समर्थन न करने का बदला ले रही हो !

पूरे हरियाणा के ग्रामीण आँचल में शायद ही कोई गाँव बिजली विभाग की दिन प्रतिदिन की छापेमारी से अछूता हो ! बीजेपी सरकार ने न केवल लोगों का जीना दूभर कर दिया है,बल्कि दिन प्रतिदिन की छापेमारी व लाखों रुपये के जुर्माने ने आम आदमी की जिंदगी को अतिकठिन बना दिया है !

3.अनाप शनाप बिजली बिलो में बढ़ोत्तरी व छापेमारी तथा जुर्माने के बावजूद बिजली की हालत पूरे हरियाणा तथा कैथल जिले में अति दयनीय है !

हरियाणा के गाँवों में बिजली मात्र 8 से 10 घंटे ही मिल पाती है तथा गाँव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है ! शहरों में 6 से 8 घंटों के अघोषित बिजली कट हैं ! बिजली की वोल्टेज फ्लकचुएशन तथा बार बार बिजली आने जाने के कारण न केवल घोर असुविधा होती है,बल्कि आए दिन टेलीविज़न,फ्रिज,कम्प्यूटर,बिजली से चलने वाली अन्य वस्तुएँ या जल जाती है या खराब हो रही हैं !भाजपा सरकार शहर तथा गाँव की इस दयनीय परिस्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है

4.हरियाणा में मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक कॉग्रेस पार्टी का शासन रहा !10 साल के इस अरसे में विषम महँगाई व बढ़ती कीमतों के बावजूद कॉग्रेस पार्टी ने बिजली की दर्रे न के बराबर बढाई ! उदाहरण के लिये :-

अगर घरेलू बिजली की बात की जाये तो मार्च 2005 से पहले (कॉग्रेस शासन से पहले)

0-40 यूनिट का दर 2.63 रुपया था और अक्टूबर 2014 में (जब कॉग्रेस ने शासन छोड़ा) यूनिट की दर 2.70 रुपया थी मतलब कॉग्रेस के 10 साल के शासन काल में 7 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई !

साल 2005 से पहले 41-300 यूनिट की दर 3.75 रुपया थी और अक्टूबर 2014 में 4.50 रुपया हो गई मतलब कॉग्रेस शासन के 10 साल में 75 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई !

साल 2005 से पहले 301-500 यूनिट दर 4.55 रुपया थी और अक्टूबर 2014 में 5.25 रुपया हो गई मतलब कॉग्रेस शासन के 10 साल में 70 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई !
साल 2005 से पहले 501 से अधिक यूनिट की दर 4.90 रुपया थी अक्टूबर 2014 में 5.98 रुपया हो गई मतलब कॉग्रेस शासन के 10 साल में 1.08 रुपया की बढ़ोत्तरी हो गई !
जैसा की उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि कॉग्रेस सरकार के 10 साल k ए कार्यकाल में कम से कम बढ़ोत्तरी 7 पैसे प्रति यूनिट थी (0-40 यूनिट)और अधिक से अधिक बढ़ोत्तरी 1.08 रुपया प्रति यूनिट थी (यानि की लगभग 10 पैसा प्रति वर्ष)! बिजली की दरें भी बिजली की खपत के आधार पर निर्धारित की जाती थी !जैसा कि हम जानते हैं,हरियाणा में 75 प्रतिशत तक घरेलू उपभोक्ता तो 0-800 यूनिट तक की श्रेणी में ही आ जाते हैं !
बिजली की दरें भी खपत के आधार पर बढ़ती थी !बिजली की दरें निर्धारित करने का फ़ार्मूला 'टेलिस्कोपिक टैरिफ 'था यानि कि उपभोक्ता ने अगर 500 यूनिट बिजली भी इस्तेमाल की तो उसकी बिजली की दर अलग अलग स्लैब प्रणाली में निर्धारित की जायेगी !पहले 40 यूनिट की दर 2.70 रुपये प्रति यूनिट होगी ! 41 से 250 यूनिट की दर 4.50 रुपये प्रति यूनिट से लगाई जायेगी ! 251 से 500 यूनिट की दर 5.25 प्रति दर के हिसाब से लगाई जायेगी ! इस प्रकार दर slaib प्रणाली के अनुसार निर्धारित की जाती थी !
दुर्भाग्यवश आपके नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को उल्टा कर नए तुगलकी फ़रमान बिजली की दरों बारे जारी कर दिए हैं !बीजेपी सरकार को अभी तक एक साल भी पूरा नहीं हुआ और बिजली की अप्रत्याशित दरों का बोझ आपने जनता के सिर पर डाल दिया है ! आज हरियाणा प्रांत में घरेलू बिजली दरों को तुगलकी फ़रमान जारी करते हुए 3 श्रेणियों में बाँट दिया गया है !
श्रेणी 1.
0 से 50 यूनिट तक की घरेलू बिजली की दरें 2.70 प्रति यूनिट और 51-100 यूनिट तक की दरें 4.50 रुपये प्रति यूनिट हैं !
श्रेणी 2.
0- 250 घरेलू यूनिट की दर 5.00 रुपया यूनिट और 251-500 यूनिट की दर 6.05 रुपये प्रति यूनिट की दर है ! इस प्रकार 250 यूनिट तक बिजली की खपत वाले उपभोक्ता पर बीजेपी सरकार ने मात्र 11 महीने में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृध्दि कर दी है ! 250 से 500 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ता पर बीजेपी सरकार ने मात्र 11 महीने में 80 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डाल दिया है !
श्रेणी 3.
500 यूनिट से अधिक घरेलू बिजली की दरों में 6.75 रुपये प्रति यूनिट है ! इस प्रकार बीजेपी सरकार ने मात्र 11 महीने में 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत वाले उपभोक्ता पर 70 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है !
सबसे ज्यादा अन्याय की बात बीजेपी सरकार द्वारा यह है कि टेलीस्कोपीक टैरिफ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है यानि कि अगर कोई उपभोक्ता 501 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसे सभी 501 यूनिट बिजली के लिए 6.75 रुपये प्रति यूनिट की लागत देनी पड़ेगी ! जबकि पहले यह राशि स्लैब प्रणाली के अनुरूप दी जाती थी और निचली स्लैब्स की बिजली खपत की दर उस स्लैब के रेट के अनुसार निर्धारित की जाती थी !
5.बीजेपी का अन्याय आम शहरी तथा घरेलू बिजली उपभोक्ता पर यहीं तक नहीं रुका !बीजेपी की सरकार अब फ्यूल सरचार्ज के नाम पर,बिजली दरों के अतिरिक्त,रुपया 1.67 प्रति यूनिट बिजली बिलो में जोड़कर दे रही है !इसके साथ साथ 5 पैसे प्रति यूनिट म्यूनिसिपल टैक्स भी है !
नतीजा यह है कि 501 यूनिट खपत करने वाले बिजली उपभोक्ता को सभी 501 यूनिट बिजली पर रुपया 8.47 प्रति यूनिट (रुपया 6.75+रुपया 1.67+.05 रुपये)की दर से वसूली की जा रही है !

बिजली की यह दर बीजेपी सरकार की बेरहमी का जीता जागता सबूत है ! बिजली की यह दर अमानवीय,अप्रासंगिक तथा आपकी सरकार की निष्ठुरता का सूचक है !

6.वाणिज्यक संस्थानों यानि दुकानों,चक्की आदि के लिए कॉग्रेस सरकार में केवल बिजली की खपत के ही पैसे लिए जाते थे ! छोटे उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क नहीं था !

भाजपा सरकार ने इस श्रेणी में भी 5 किलोवाट तक बिजली की दरें रुपए 5.85 से बढाकर रुपए 6.05 कर दी यानि कि हर साधारण व्यापरी की दुकान के बिल में 20 पैसा प्रति यूनिट की वृध्दि की !5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक की दरें भी रुपये 6.10 से बढाकर रुपए 6.75 कर दी यानि कि मध्यम दर्जे के सभी दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थानों में बीजेपी द्वारा 65 पैसा प्रति यूनिट दरों में इजाफा कर दिया गया !लगभग यही स्थिति लघु उधोगों की भी है !

बीजेपी सरकार के 11 महीने में बिजली का आम उपभोक्ता,चाहे वो घरेलू हो या दुकानदार,त्राहि त्राहि कर रहा है ! एक तरफ़ बिजली उपलब्ध ही नहीं,तो दूसरी तरफ़ बिजलीकर्मी की छापेमारी ने हरियाणा के निवासियों का जीवन दूभर कर दिया है ! सबसे कमरतोड़ तो 8.47 रुपए प्रति यूनिट की घरेलू बिजली की भी दरें हैं,जो 501 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ता को देनी पड़ती है !

इसलिये खट्टर साहब बिजली की दरों को वापस लिया जाए,बिजली की छापेमारी बँद की जाए तथा बिजली की उपलब्धता सुनिश्चत की जाए